भारत में 1.22 करोड़ से अधिक पाठक (IRS 2017)

PUNJAB KESARI

पंजाब केसरी

SUNDAY, 9 JUNE 2019. तापमान अधिकतम 43° | न्यूनतम 29° आज मौसम साफ रहेगा। सूर्योदय 05.23 | सूर्यास्त 07.17

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लांच होंगे 5 प्रोजेक्ट

■ सेक्टर-93 के हाउसिंग प्रोजेक्ट में होगा करोड़ों का निवेश

गुड़गांव, 8 जून (ब्यूरो): प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती श्रेणी के पांच प्रोजेक्ट को गुड़गांव में लांच करने की तैयारी है। इसके लिए सेक्टर 93 में एमआरजी वर्ल्ड नाम की रियल एस्टेट कंपनी करीब दो सौ करोड़ का निवेश करने जा रही है।

इन पांचों प्रोजेक्ट में करीब सात से अधिक यूनिटों का निर्माण किया जाना है जिसे मोदी सरकार के सबके लिए आवास योजना 2022 के लक्ष्य में पूर्ति के लिए बनाया जाएगा। इसी तरह नई सरकार आने के बाद केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2019-2020 में 25 बीपीएस की कटौती से होम लोन सस्ता होने की उम्मीद से गुड़गांव के रियल एस्टेट बाजार में तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। नेशनल काउंसिल फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग के मनोज गौड़ इसे स्वागत योग्य कदम बताया है। वह कहते हैं कि इस कदम से निश्चित रूप से उन बैंकों को लाभ होगा जो अंतत: रियल एस्टेट सेक्टर को ऋण दे सकते हैं। दरों में तीसरी बार कमी की गई है जिससे आम आदमी के पहुंच में आवास आएंगे। हालांकि पिछली कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया था, इसलिए हमें इंतजार करना होगा। हाउसिंग डॉटकॉम के मणिरंगराजन कहते हैं कि रेपो रेट में कटौती से खरीददारों को भारी

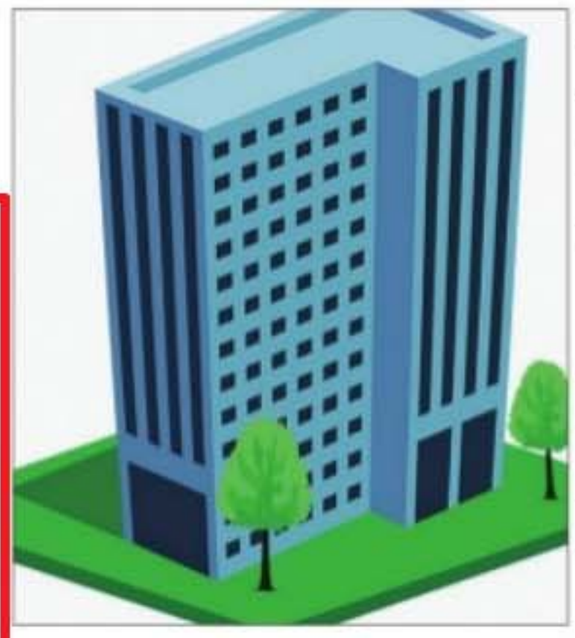

फायदा होगा और बैंकों को लोन देना आसान होगा।

निर्माणाधीन संपत्तियों के लिए जीएसटी की दरों में हालिया कमी के साथ अब कम ब्याज दरों से अंतिम उपयोगकर्ता की मांग को निश्चित रूप से पूरी होनी चाहिए। प्रमुख रियल एस्टेट कारोबारी दीपक कपूर कहते हैं कि आरबीआई ने इस वित्तीय वर्ष में रेपो दर को कम करने के साथ ऋण देने की दिशा में नरम रुख दिखाया है। इसके अलावा, सरकार ने बजट 2019 में अफोर्डेबल सेगमेंट की ओर जो रुख दिखाया, जिसमें आयकर छूट को 5 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया था।

रीयलिस्टिक रियाल्टर के पंकज जैन का कहना है कि वास्तव में रियल एस्टेट क्षेत्र में डिमांड को तेजी देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इससे बैंकों को रेट कट का लाभ ग्राहकों को घर और अन्य तरह के लोन पर देने में मदद मिलेगी।

सरकारी आंकड़ों में 155 प्रोजेक्ट अधूरे

हरियाणा आवास बोर्ड ने गुड़गांव में 1719 आर्थिक रुप से कमजोर वर्गो के लिए आवास निर्माण की तैयारी शुरु कर दी है। जिसका सीधा असर गुड़गांव के कारोबार पर पड़ने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। हांलाकि गुड़गांव में सरकारी आंकड़ों में 155 प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है जिनमें सवा दो लाख आवासों का निर्माण किया जाना है। जबकि तश्वीर का दूसरा पहलू यह है कि यहां पर एक लाख से अधिक खरीददार अब भी है जो अपने सपनों के आशियाने की आस लगाए आए दिन धरना-प्रदर्शन करने पर विवश है। यहां पर जहां आवासीय, व्यावसायिक, किफायती आवासों से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल आवास योजना के तमाम प्रोजेक्ट अधर में हैं। बिल्डरों के इंद्रधनुषी सपनों में खोकर यहां पर महंगे फ्लैट लोग खरीद तो लेते हैं लेकिन पैसा दे दिए जाने के बाद उनका सपना चकनाचूर हो जाता है। गुड़गांव में तकरीबन एक लाख लोगों को अपने आवासों का इंतजार है जिनमें करीब 60 से 70 हजार ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने यूनिट की 90 फीसदी से अधिक रकम जमा कर दिया है और दशक से अधिक समय हो गए लेकिन उन्हें आवास नहीं मिल पाया।

नेशनल काउंसिल फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग के मनोज गौड़ इसे स्वागत योग्य कदम बताया है। वह कहते हैं कि इस कदम से निश्चित रूप से उन बैंकों को लाभ होगा जो अंतत: रियल एस्टेट सेक्टर को ऋण दे सकते हैं। दरों में तीसरी बार कमी की गई है जिससे आम आदमी के पहुंच में आवास आएंगे। हालांकि पिछली कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया था, इसलिए हमें इंतजार करना होगा।